

रजिस्टर्ड नं ० ल ०३३/एस ० एम ० १४.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 14 अगस्त, 1989/23 थावण, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खंड)

अधिसूचनाएं

शिमला-२, ६ सितम्बर, 1988

सं ० एल ०एल ०आर ०-९, ८८.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा ३द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एकट, 1968 (1969 का 8)” के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव ।

## हिमाचल प्रदेश जल प्रदाय अधिनियम, 1968

( 1969 का 8 )

( 24 मार्च, 1969 ) ( 31-7-88 को यथाविद्यमान )

हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय कार्यों के विकास, नियन्त्रण और प्रबन्ध का उपबन्ध करन के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल प्रदाय अधिनियम, 1968 है ।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ ।

( 2 ) इसका विस्तार सम्बूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

( 3 ) यह तुरत्त प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विव्यु विव्यु परिभाषाएँ न हो—

- (i) “हिताधिकारी” से किसी जल प्रदाय स्कीम के बारे में, कोई स्थानीय प्राधिकरण अभिप्रेत है जो तत्समय ऐसी स्कीम से प्रसुविधा प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करेगा ;
- (ii) “उपभोक्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे हिताधिकारी से, जिसे जलप्रदाय स्कीम सौंपी जा सके, जल लेता है या जो ऐसी जल प्रदाय स्कीम से जल लेता है जिसका प्रबन्ध सीधा सरकार द्वारा किया जाता है;

स्पष्टीकरण :—उपभोक्ता के अन्तर्गत हिताधिकारी नहीं है ।

- ( 3 ) “सहकारी सोसाइटी” से सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 13 ) या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ( 1966 का 31 ) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 ( 1961 का 25 ) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है;
- ( 4 ) “राजपत्र” से हिमाचल प्रदेश राजपत्र अभिप्रेत है;
- ( 5 ) “सरकार” या “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- ( 6 ) “ग्राम पंचायत” “पंचायत समिति” और “जिला परिषद्” के बे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 ( 1970 का 19 ) में इन अभिव्यक्तियों के क्रमशः हैं;
- ( 7 ) “स्थानीय प्राधिकरण” से सहकारी सोसाइटी, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका या कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा जल प्रदाय स्कीम का विकास अथवा नियन्त्रण या प्रबन्ध सौंपा गया है;
- ( 8 ) “नगर पालिका” और “ग्रामसूचित क्षेत्र समिति” के बे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 ( 1968 का 19 ) में इन अभिव्यक्तियों के क्रमशः हैं;

- (9) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (10) "ग्रामीण क्षेत्र" से शहरी क्षेत्र का अपवर्जन करके, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;
- (11) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (12) "स्कीम" से धारा 3 के अधीन आरम्भ की गई जल प्रदाय स्कीम अभिप्रेत है;
- (13) "शहरी क्षेत्र" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट नगर अभिप्रेत है;
- (14) "जल रेट" से सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन तत्समय उद्गृहीत प्रभार अभिप्रेत है;

जल प्रदाय स्कीम।

3. राज्य सरकार, समय-समय पर, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनता के फायदे के लिए पर्यजल स्कीमें आरम्भ कर सकेंगी और विद्यमान जल प्रदाय का अनुरक्षण और सुधार कर सकेंगी।

4.

×

×

×

×

जल रेट का उद्ग्रहण।

5. राज्य सरकार, सरकार द्वारा सीधे प्रबन्ध को जा रही जलप्रदाय स्कीम से या ऐसे हिताधिकारी द्वारा, जिसे स्कीम सौंपी जाए, उपभोक्ता को प्रदाय किए गए जल के लिए, ऐसी दरों पर जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जल रेट उद्गृहीत करेगी।

(2) व्यक्तियों से जल प्रभार की वसूली फ्लैट रेट या मीटर कनैक्शन के आधार पर की जाएगी।

(3) उद्गृहीत जल रेट, यदि देय होने के समय संदर्भ नहीं किया जाता है तो यह ऐसे वसूल किया जाए मानों कि यह भू-राजस्व की बकाया हो।

जल प्रदाय स्कीमों को सौंना।

6. (1) जहां स्थानीय प्राधिकरण किसी स्कीम को हिताधिकारी के रूप में ग्रहण करने और अनुरक्षित करने के लिए तैयार हो, राज्य सरकार, ऐसी स्कीम का विकास, प्रबन्ध या नियंत्रण ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए सौंपेंगी, जैसी राज्य सरकार उचित समझे।

(2) स्थानीय प्राधिकरण जो स्कीम को इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन ग्रहण करता है, ऐसे जल रेट निर्धारित करेगा जैसे वह आवश्यक समझे और ऐसी स्कीम के पर्याप्त प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जल रेट, जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निश्चित किया जाए, किसी भी दशा में, सरकार द्वारा धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट जल रेट से अधिक नहीं होगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत जल रेट, यदि कोई हो, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे रेट के नियत किए जान पर प्रभावहीन हो जाएग।

7. (1) हिताधिकारियों द्वारा धारा 6 के अधीन ग्रहण की गई सभी स्कीमें, राज्य सरकार के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी और स्कीम को कार्यप्रणाली का नियंत्रकालिक नियंत्रण राज्य सरकार के अधिकारण द्वारा विहित रीति में किया जाएगा ।

राज्य सरकार द्वारा सामान्य नियंत्रण ।

(2) यदि हिताधिकारी इस अधिनियम के अधीन या इस द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या निरन्तर व्यतिक्रम करता है, या अपनी शक्तियों से अधिक या इनका दुरुपयोग करता है या स्कीम का दक्षतापूर्ण रीति में अनुरक्षण करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, जिसमें ऐसा करने के लिए कारणों का विवरण दिया जाएगा, हिताधिकारी में स्कीम का विकास, प्रबन्ध या नियंत्रण वापस ले सकेगी :

परन्तु उप-धारा (2) में वर्णित अधिसूचना के जारी किए जाने में पूर्व, हिताधिकारी को, विहित रीति में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध युक्तियुक्त कारण बताने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) जब विकास, प्रबन्ध और नियंत्रण इस तरह वापस लिया जाए, तो इसके निम्नलिखित आगामी परिणाम होंगे :—

- (क) स्कीम का विकास, प्रबन्ध और नियंत्रण अधिसूचना की तरीख से राज्य सरकार में निहित होगा;
- (ख) हिताधिकारी द्वारा उदाहृत जल रेट तब तक प्रवर्तन में रहेगा, जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए गए जल रेट से प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता ।

(4) राज्य सरकार, स्थिति का ऐसे अन्तराल पर जैसा कि विहित किया जाए, किन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, पुनरीक्षण करेगी और यदि यह किसी समय उचित समझ तो पुनः स्कीम हिताधिकारी को सौंपेगी ।

8. (1) ऐसा उपभोक्ता जिसके नाम पर जल कनैक्शन रजिस्ट्रीकूट है, हिताधिकारी को जल रेट संदर्भ करने के लिए दायी होगा, यदि स्कीम प्रबन्ध या जल प्रदाय के नियंत्रण के लिए कोई हिताधिकारी को सौंपी गई है ।

उपभोक्ता का दायित्व ।

(2) यदि कोई हिताधिकारी नहीं है और जल प्रदाय स्कीम का प्रबन्ध सीधा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हो, तो उपभोक्ता राज्य सरकार को जल रेट संदर्भ करन का दायी होगा ।

9. राज्य सरकार को अनुसूची में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या विवरण करने की शक्ति होगी ।

अनुसूची में उपांतरण करने को राज्य सरकार की शक्तियां ।

10. (1) जो कोई भी व्यक्ति, उचित प्राधिकार के बिना और स्वेच्छा से निम्नलिखित कार्य करता है, अर्थात् :—

- (क) किसी जल प्रदाय स्कीम के जल को इस प्रकार अल्ट या कनुषित करता है कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए सामान्यतः इसे प्रयुक्त किया जाता है, कम उपयुक्त हो जाता है;

अरुद्ध नियम के अधीन अपराध ।

(ख) राज्य सरकार या हिताधिकारी द्वारा जल प्रदाय स्कीम के अधीन शोधम, भण्डारकरण या पूर्ति के लिए निर्मित, सुरक्षित या निर्मित, सुरक्षित या नियन्त्रित किसी बाध, कुएं, तटबन्ध, स्लूस, जलाशय, नाली, नल, संरचना या अन्य कार्यों को नष्ट करता है, तुकसान पहुंचाता है, परिवर्तित करता है, बाधा या क्षति पहुंचाता है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी ऐसे नियम का अतिक्रमण करता है जिसके भंग के लिए शास्ति उपगत हों, तो ऐसे वर्ग के मैजिस्ट्रेट द्वारा, जैसा राज्य सरकार विहित रीति में इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे, दोषसिद्ध किए जाने पर पांच सौ रुपये से अनधिक जुर्माने या एक मास से अनधिक कारावास या दोनों के लिए दायी होगा।

(2) इस में इसकी कोई भी बात, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने से निवारित नहीं करेगी, किन्तु किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जाएगा।

(3) इसमें इसकी कोई भी बात, यथास्थिति, राज्य सरकार या किसी हिताधिकारी को, इस धारा की उपधारा (1) में वर्णित किसी अपराध को करने वाले व्यक्ति से, तुकसानी वसूल करने से निवारित नहीं करेगी।

नियम बनाने की जाकित।

11. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम इस प्रकार विहित कर सकेंगे:—

(क) वे सिद्धान्त और शर्तें जिन पर धारा 3 के अधीन स्कीम आरम्भ की जाएंगी;

(ख) वे सिद्धान्त जिनका धारा 5 के अधीन जल रेट नियत करने में अनुसरण किया जाएगा;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन जल प्रदाय स्कीम स्थानीय प्राविकरण को सौंपी जाएंगी; और

(घ) धारा 6 के अधीन जल प्रदाय स्कीम के हिताधिकारी द्वारा दक्षतापूर्ण प्रवन्ध सुनिश्चित करन के लिए, धारा 5 के अधीन नियुक्त की गई समिति; और

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथापीद्वा विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरा हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या

निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

12. इस अधिनियम के उपबन्ध, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा उपयोग किए जा रहे अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे ।

13. (1) प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त “दि हिमाचल प्रदेश बाटर सप्लाई एक्ट, 1956 (1956 का 15) का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई कोई वात या कारंवाई जारी किए गए किसी आदेश, अधिसूचना और बनाए गए नियम सहित, जहां तक इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त तत्स्थानी शक्तियों के प्रयोग में की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

जिला महासू

ठियोग, रामपुर, सोलन, जुबल और अर्की ।

जिला सिरमौर

नाहन, सराहन, पांवटा साहिव, माजरा और राजगढ़ ।

जिला चम्बा

चम्बा, भरमौर, चौवाड़ी, तिसा और भान्दल ।

जिला मण्डी

मण्डी, जोगिन्दरनगर, सरकाधाट, सुन्दरनगर और करसोग ।

जिला बिलासपुर

नया बिलासपुर टाउनशिप और धुमारवीं ।

जिला किन्नौर

पिंडो, करछम, सांगला, कल्पा, पवारी, पांगी और कानम ।

जिला कांगड़ा

कांगड़ा, धर्मशाला, देहरा गोपीपुर, पालमपुर, बैजनाथ, ऊना, और नूरपुर ।

नगरपालिका  
निरसन अधीन  
व्यावृत्तियां ।

जिला शिमला

शिमला, कण्डाधाट, नालागढ़, धर्मपुर और कसौली ।

जिला कुल्लू

कुल्लू भनाली, बन्जार, निरमण, आउटर सिराज में आनी ।

लाहौल और स्थिति

किलोग्राम और काजा ।

शिमला-171002, 6 सितम्बर, 1988

सं0 एल0 एल0 आर0- (11)/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपुरक-उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश रिक्वीजिशनिंग एण्ड ऐक्वीजीशन आफ इम्मूवैवल प्राप्टी एक्ट, 1972 (1973 का 20)” क, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करन का आदेश दत हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना आवश्यक हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1972

(1973 का 20)

(13 जुलाई, 1988) (10-8-1988 को यथा विद्यमान)।

राज्य के प्रयोजनों के लिए स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेज़स्वे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1972 है।  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।  
(3) यह इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, दस वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
कालावधि।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपक्रित न हो,—

परिभाषाएं।

- (क) “अधिनियम” से धारा 10 के अधीन मध्यस्थ द्वारा किया गया कोई अधिनियम अभिप्रेत है;
- (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन, एसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के पालन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्तिया प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) “सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (घ) “भू-स्वामी” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय किसी परिसर का चाहे अपने वास्ते या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते या उसको और से, या उसके फायदे के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यासों संरक्षण या रिसोवर के रूप में किराया प्राप्त करने का हकदार है, या जो इस प्रकार किराया प्राप्त करता या प्राप्त करने का हकदार होता, यदि परिसर किसी अभिवारो को किराए पर दिए गए होते;
- (ङ) “शासकीय राजपत्र” से राजपत्र हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (च) किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में “हितबद्ध व्यक्ति” पद के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन, उस सम्पत्ति के अधिग्रहण या अर्जन, कारण संदेय में हित का दावा करने वाले या दावा करने का हकदार, सभी व्यक्ति हैं;
- (छ) “परिसर” से कोई इमारत या इमारत का भाग अभिप्रेत है; और
  - (i) ऐसी इमारत या इमारत के भाग से सम्बंधित उद्यान, मैदान, उपगृह, यदि कोई हो;
  - (ii) ऐसी इमारत या इमारत के भाग के उपभोग के लिए उसमें को गई कोई फिटिंग;
- इसके अन्तर्गत है;
- (ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "सम्पत्ति" से हर प्रकार की स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत है और इसके प्रत्यर्थी ऐसी सम्पत्ति में या उसके बारे में कोई अधिकार है,

(ज) "अभिधारी" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से किसी परिसर का किराया संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसे उप-अभिधारी और अन्य व्यक्ति हैं जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा अभिधारी के अधीन हक व्युत्पन्न हुआ है।

स्थावर-  
सम्पत्ति का  
अधिग्रहण  
करने की  
शक्ति ।

3. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि कोई सम्पत्ति किसी लोक प्रयोजन के लिए, जो राज्य का प्रयोजन है आवश्यक है या आवश्यक होनी संभाव्य है और सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, तो सक्षम प्राधिकारी,—

(क) स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति से, जिसका सम्पत्ति पर कब्जा हो, लिखित नोटिस द्वारा (उसमें अधिग्रहण का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करते हुए) ऐसे नोटिस की उस पर तामील होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर वह कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि सम्पत्ति क्यों अधिगृहीत नहीं की जानी जाहिए; और

(ख) आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि पूर्व अनुमति के न तो सम्पत्ति का स्वामी, न कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना सम्पत्ति का व्यवहार करेगा या उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करेगा, या अभिधारी को किराए पर देगा, जब तक कि दो मास से अनधिक ऐसी अवधि का अवसान नहीं हो जाता, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) यदि, सम्पत्ति में हितबद्ध या सम्पत्ति पर कब्जा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए हेतुक पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह लिखित आदेश द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जो अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

परन्तु ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग का,—

(क) जिसका उसके स्वामी द्वारा वास्तव में अपने या अपने कुटुम्ब के निवास के रूप में प्रयोग किया जाता है; या

(ख) जिसका या तो जनता द्वारा अनन्यतः धार्मिक पूजा के लिए या पाठ्यालाल, अस्पताल, लोक पुस्तकालय या अनाथालय के प्रबन्ध से संबंधित व्यक्तियों द्वारा वास सुविधा के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, अधिग्रहण नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां अधिगृहीत सम्पत्ति ऐसे परिसर से मिलकर वर्ती है, जिनका प्रयोग अभिधारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की तरीक से टीक पूर्व दो मास से अन्यून अवधि के लिए निवास के रूप में किया जा रहा है,। वहां सम्पत्ति का कब्जा तब तक लिया जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभिधारी के लिए ऐसी आनुकूलिक वास सुविधा की व्यवस्था नहीं कर दी जाती जो उसकी राय में उपयुक्त हो।

अधिगृहित सम्पत्ति का कब्जा लेने की शक्ति ।

4. (1) जहां धारा 3 के अधीन कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की गई है, वहां सक्षम प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति को भी, जिसका सम्पत्ति पर कब्जा हो, उस सम्पत्ति का कब्जा, सक्षम प्राधिकारी को या उस द्वारा इस निमित्त सम्मुक्त रूप

से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, नोटिस की तरीकी से तीस दिन के भीतर अन्धर्पत्ति या परिदत्त करने का आदेश द सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का अनुपालन करने से इनकार करता है या असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी सम्पत्ति का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो।

(3) उप-धारा (2) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे का परिदान, उस सम्पत्ति के बारे में सरकार का समस्त दायित्वों से उन्मोचन होगा, किन्तु यह उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिनका कि वह विधि की समयक प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विश्वद्वं प्रवृत्त करने के हकदार है जिसे सम्पत्ति का कब्जा दिया जाता है।

(4) जहां कोई व्यक्ति जिसको अधिगृहीत सम्पत्ति का कब्जा दिया जाना है, उपलब्ध नहीं है और उसकी ओर से परिदान स्वीकार करने के लिए उसका कोई अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति सशक्त नहीं है, सक्षम प्राधिकारी एक नोटिस यह घोषणा करते हुए कि सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जाती है, सम्पत्ति के किसी सहज दृश्य भाग पर लगवाएगा और राजपत्र में भी नोटिस प्रकाशित कराएगा।

(5) जब उप-धारा (4) में निर्दिष्ट, नोटिस राजपत्र में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति, ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से अधिग्रहण के अधीन नहीं रह जाएगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसका परिदान उस व्यक्ति को किया गया है जो उसके कब्जे का हकदार है और सरकार उस तारीख के पश्चात किसी भी अवधि के लिए किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(6) जहां इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत कोई सम्पत्ति या उसका कोई महत्व-पूर्ण भाग अग्नि, भूम्प, आंधी, बाढ़ या सेना की संक्रिया या भीड़ द्वारा हिसा या अन्य अप्रतिरोध्य बल के कारण पूर्णतः नष्ट हो जाता है या सारतः और स्थायी रूप से उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसे अधिगृहीत किया गया था अनुपयुक्त हो जाता है, वहां सरकार के विकल्प पर, अधिग्रहण, विधि शून्य होगा।

परन्तु इस उप-धारा का फायदा सरकार को वहां उपलब्ध नहीं होगा जहां ऐसी सम्पत्ति को धृति सरकार के दोषपूर्ण कार्य या व्यतिक्रम से हुई हो।

5. (1) धारा 3 के अधीन अधिगृहीत समस्त सम्पत्ति का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा जो अधिग्रहण के नोटिस में वर्णित हो।

अधिगृहीत सम्पत्ति पर अधिकार।

(2) जहां धारा 3 के अधीन कोई परिसर अधिगृहीत किए गए हैं, सक्षम प्राधिकारी, भू-स्वामी को आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी मुरम्मत जो आवश्यक हो और उस परिक्षेत्र में भू-स्वामियों द्वारा प्रायः को जाती हो, और जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए युक्ति-युक्त समय के भीतर करेगा जो उसमें वर्णित किया जाए, और यदि भू-स्वामी ऐसे आदेश के अनुसरण में किसी मुरम्मत को करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, अदिश में विनिर्दिष्ट मरम्मत को -भू-स्वामी के खर्च पर करवा सकेगा और उसकी लागत की कटौती वसूली की किसी अन्य रोति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू-स्वामी को संदेश प्रतिकर में से की जा सकेगी।

अधिग्रहण से निर्मुक्त। 6. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अधिग्रहण से निर्मुक्त कर सकेगा और सम्पत्ति को, यथासम्भव उसनी अच्छी हालत में, जितनी में वह उस समय थी जब उसका कब्जा लिया गया था, केवल युक्तियुक्त टूट-फूट और अप्रतिरोध बल द्वारा काश्ति परिवर्तनों के अधीन रहते हुए प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु जहां वे प्रयोजन, जिन के लिए अधिग्रहणीत सम्पत्ति का प्रयोग किया जा रहा था, अस्तित्वहीन हो जाते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी, उस सम्पत्ति को, यदि सम्पत्ति धारा 9 के अधीन अर्जित न की ई हो, अधिग्रहण से यथाशीघ्र, निर्मुक्त करेगा ।

(2) जहां कोई सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जाती है, सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जाति के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह किसी मामले में करना या करना आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसको सम्पत्ति का कब्जा दिया जाएगा, और ऐसा कब्जा यथासाध्य, उस व्यक्ति को जिससे अधिग्रहण के समय कब्जा लिया गया था या ऐसे व्यक्ति के हित उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा ।

अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए आवेदन ।

7. (1) किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात्, स्वामी या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इसे अधिग्रहण से निर्मुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आवेदन सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व किया जा सकेगा, यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिन पर कि स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कारण बताने के लिए दिए गए अवसर पर जोर न दे सका हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति से, ऐसी जानकारी मंगाने पर जैसी कि वह आवश्यक समझे, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे ।

अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए अतिरिक्त आवेदन ।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 7 के अधीन अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए आवेदन के नामंजूर किए जाने और धारा 13 के अधीन सरकार के समक्ष दाखिल अपील के भी नामंजूर किए जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए अगला आवेदन पत्र दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के अवसान पर्यन्त ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, प्रथम अपील की नामंजूरी से दो वर्ष के भीतर दूसरा आवेदन किया जा सकेगा, यदि तत्पश्चात् ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिन पर वह पूर्ववर्ती आवेदन में जोर न दे सका हो ।

अधिग्रहित सम्पत्ति को अर्जित करने की शक्ति ।

9. (1) जहां कोई सम्पत्ति अधिग्रहण के अधीन है, वहां यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक प्रयोजन के लिए सम्पत्ति का अर्जन करना आवश्यक है, तो वह राजपत्र में उस आशय का नोटिस प्रकाशित करके कि सरकार ने इस धारा के अनुसरण में सम्पत्ति अर्जित करने का विनिश्चय किया है, ऐसी सम्पत्ति को किसी भी समय अर्जित कर सकेगी :

पश्चत् ऐसा नोटिस जारी करने से पूर्व मरकार, स्वामी या किसी व्यक्ति में, जो सरकार की राय में ऐसी सम्पत्ति में हितवद्ध हो या कारण वताने की अपेक्षा करेगी कि सम्पत्ति क्यों अर्जित नहीं की जानी चाहिए, सम्पत्ति में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाएं गए हेतुक पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् और पक्षकारों का सुन-वार्ड का अवमर देने के पश्चात् मरकार, ऐसे श्रादेश पारित कर सकेगी जो वह उचित समझे ।

(2) जब यथापूर्वोक्त नोटिम राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो अधिगृहीत सम्पत्ति, उस दिन को और उसके प्रारम्भ से जिसको नोटिम इम प्रकार प्रकाशित किया जाता है, सभी विलंगमों से मुक्त आत्मतिक रूप से मरकार में निहित हो जाएगी और ऐसी सम्पत्ति की अधिग्रहण-अवधि समाप्त हो जाएगी ।

(3) इस धारा के अधीन निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाए, कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) जहां, अधिग्रहण की अवधि के दौरान सम्पत्ति पर, में या ऊपर पूर्णतः या भागतः मरकार के खर्च पर कोई संकर्म किए गए हों और मरकार विनिश्चय करती है कि ऐसे संकर्मों का मूल्य या प्रयोग करने का अधिकार राज्य के प्रयोजनों के लिए मुरक्खित या परिरक्षित किया जाना चाहिए; या
- (ख) जहां सम्पत्ति को उस हालत में प्रत्यावर्तित करने की लागत, जिसमें वह अधिग्रहण के सभी थी, सरकार के अवधारणानुसार अत्यधिक होती और स्वामी सम्पत्ति को ऐसे प्रत्यावर्तित किए जाने के लिए प्रतिकर के संदय के बिना सम्पत्ति की अधिग्रहण से निर्मुक्ति को स्वीकार करने से इन्कार करता है ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन सरकार का कोई विनिश्चय या अवधारण अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में वह प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(5) उप-धारा (3) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए “संकर्म” के अन्तर्गत भवन संरचनाएं और हर प्रकार का सुधार है ।

10. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई सम्पत्ति अधिगृहीत या अर्जित की जाती है, वहां प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी राशि इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त रीति और सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) जहां प्रतिकर की राशि करार द्वारा निश्चित की जा सकती है, वहां यह करार के अनुसार संदत्त की जाएगी;
- (ख) जहां इस प्रकार का करार नहीं हो पाता है, वहां सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है, या उस रूप में नियुक्ति के लिए अहित है, मध्यस्थ के रूप ने नियुक्त करेगी;
- (ग) सरकार किसी विशिष्ट भागले में ऐसे व्यक्ति को जिसे अधिगृहीत या अर्जित सम्पत्ति की प्रकृति के बारे में विशेषज्ञीय जानकारी प्राप्त है, मध्यस्थ की सहायता करने के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकेगी और जहां ऐसा नाम निर्देशन किया जाता है, वहां वह व्यक्ति जिसे प्रतिकर दिया जाना है, उस प्रयोजन के लिए किसी मूल्यांकक (अमेसर) को नाम निर्देशित सकेगा;

प्रतिकर  
अवधारण  
करने के  
सिद्धांत  
और ढंग ।

(घ) मध्यस्थ के समक्ष कार्यशालियों के प्रारम्भ पर, सरकार और वह व्यक्ति जिसे प्रतिकर दिया जाना है, यह बताएंगे कि उनकी अधीनी-अपनी राय में प्रतिकर की उचित रकम क्या है;

(ङ) मध्यस्थ विवाद की मुनवाई के पश्चात् प्रतिकर की रकम को जो उसे न्यायसंगत बताती होती है, अवधारणा करते हुए और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिन्हें ऐसा प्रतिकर दिया जाएगा, अधिनिर्णय देगा, और अधिनिर्णय देने में वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को और उप-धारा (2) और (3) के उपबन्धों का वहां तक जहां तक वे लागू होते हैं, ध्यान रखेगा;

(च) जहां इस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के बारे में, जो प्रतिकर के हकदार हैं, विवाद है, वहां मध्यस्थ ऐसे विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि मध्यस्थ को यह मालूम होता है कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार हैं, तो वह उसकी रकम को ऐसे व्यक्तियों में प्रभागित कर देगा;

(छ) मध्यस्थम अधिनियम, 1940 (1940 का 10) की कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थों को लागू नहीं होगी।

(2) किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए देय प्रतिकर की रकम निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) अधिग्रहण की कालावधि की बाबत इतना आवर्ती संदाय, जितना उस किराये के बराबर है जो उस सम्पत्ति के उपयोग और अधिभोग के लिए उस दशा में देय होता जिसमें कि वह सम्पत्ति उस कालावधि के लिए पट्टे पर ली गई होती; और

(ख) ऐसी राशि या राशियां यदि कोई हों, जो निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों में हितबद्ध व्यक्ति की प्रतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक पाई जाएं, अर्थात् :—

- (i) अधिग्रहण के कारण हुई धन की हानि;
- (ii) अधिगृहीत परिसर को खाली करने में हुए व्यय;
- (iii) अधिग्रहण से निर्मुक्त होने पर परिसरों पर पुनः अधिभोग करने में लगे व्यय;
- (iv) अधिग्रहण की कालावधि के दौरान सम्पत्ति पर (साधारण टूट-फूट से अन्यथा) हुई नुस्खानी, जिनके अन्तर्गत वे व्यय आते हैं। जिन्हें सम्पत्ति को उस दशा में प्रत्यावर्तित करने में उपगत करना पड़ा है, जिसमें वह अधिग्रहण के समय थी।

(3) धारा 9 के अधीन सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए देय प्रतिकर वह कीमत होगी जिस पर अधिगृहीत सम्पत्ति खुले बाजार में तब बिकती, जब कि वह उसी दशा में रहती, जिसमें वह अधिग्रहण के समय थी और अधिग्रहण की तारीख को बेचो गई होती।

(4) जहां कहीं प्रतिकर में कई व्यक्ति हितबद्ध हैं, वहां सरकार के लिए यातो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन पर, स्वयं उसे या किसी अन्य मध्यस्थ को विवाद के सम्बन्ध में अधिनिर्णय देने के लिए नियुक्त करना, विधिपूर्ण होगा।

प्रतिकर का संदाय।

11. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, अधिनिर्णय के अधीन देय प्रतिकर की रकम सक्षम प्रत्यकारी द्वारा उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को, ऐसी रीति में आंग एस ममय क भीतर, जो अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट किया जाए, संदर्त को जाएगी या दी जाएगी।

12. (1) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए अधिग्रहण आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण में निवारित हुआ था, तो वह उक्त इक्कीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर सरकार, सक्षम प्राधिकारी में रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवाराद देने और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे और सरकार का आदेश अन्तिम होगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अपील की जाए, सरकार सक्षम प्राधिकारी के आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिए और ऐसी जरूरत पर रोक सकेगी जैसी वह उचित समझे ।

13. (1) धारा 7 और 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर, सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार, यदि इसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से, पर्याप्त हेतुक से, निवारित हुआ था तो वह उक्त इक्कीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर सरकार, सक्षम प्राधिकारी में रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे और सरकार के आदेश अन्तिम होंगे ।

14. धारा 10 के अधीन किए गए मध्यस्थ के अधिनिर्णय से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसे अधिनिर्णय की तारीख से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। जिसकी अधिगृहीत या अर्जित सम्पत्ति स्थित है :

परन्तु उच्च न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त हेतुक से समय पर अपील दाखिल करने से निवारित रहा था, तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा ।

15. सक्षम प्राधिकारी और धारा 10 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ को, यथास्थिति, जांच या मध्यस्थम कार्यवाही करते समय निन्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की व सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन बाद का विचारण करते समय उस प्राप्त होती हैं, अर्थात् :-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा कराना;
- (ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे पेश किया जाना;
- (ग) साक्ष्य का शपथ पर लिया जाना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख को अव्यवेक्षा करना; और

अधिग्रहण आदेशों से अपीलें ।

अधिग्रहण से नियुक्ति के लिए आवाद-दाने को नाम-जूर करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अपील ।

प्रतिकर संबंधी अधिनिर्णयों से अपील ।

सक्षम प्राधिकारी और मध्यस्थ को सिविल न्यायालयों की कतिपय शक्तियों का प्राप्त होना ।

## (ड) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

जानकारी  
अभिनियम करने की  
शक्ति।

16. सरकार या सक्षम प्राधिकारी, धारा 3 या धारा 6, या धारा 9 या धारा 10, के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से कि वह व्यक्ति ऐसे अधिकारी को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपने पास की ऐसी कोई जानकारी को देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत या अर्जित की जाने के लिए आशयित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट को जाए।

प्रवेश श्रीर  
निरीक्षण  
करने की  
शक्ति।

17. सक्षम प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष, आदेश द्वारा सशक्त कोई अधिकारी यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश दिया जाना चाहिए और यदि दिया जाना चाहिए तो किस रीति में या इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से किसी सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

नोटिस और  
आदेशों की  
तारीख।

18. (1) इस धारा और किंहीं नियमों के उपबन्धों के, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या दिया गया प्रत्येक नोटिस या आदेश, —

- (क) साधारण स्वल्प या व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करने वाले नोटिस या आदेश की दशा में राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा;
- (ख) किसी व्यष्टिक, निगम या फर्म को प्रभावित करने वाले किसी नोटिस या आदेश की दशा में उसकी तामील, सिविल प्रक्रिया मंहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसंची के, धर्यास्थिति, आदेश XXIX के नियम 2 या आदेश XXX के नियम 3 में समन की तामील के लिए उपबन्धित रीति में की जाएगी; और
- (ग) व्यष्टिक व्यक्ति (जो निगम या फर्म नहीं है) को प्रभावित करने वाले नोटिस या आदेश की दशा में उसकी तामील, ऐसे व्यक्ति पर —

- (i) इसे उस व्यक्ति को परिदत्त या निविदित करके;
- (ii) यदि इस प्रकार उसे परिदत्त या निविदित नहीं की जा सकती है, तो उसे ऐसे व्यक्ति के किसी अधिकारी या कुटुम्ब के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य को परिदत्त या निविदित करके या उसकी एक प्रति उस परिसर क, जिसके बारे में यह जात है कि उसमें उस व्यक्ति ने अन्तिम बार निवास किया है, या कारबार किया है या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभों के लिए कार्य किया है, बाहर या किसी सहज दृश्य भाग पर लगा कर या, इन साधनों द्वारा तामील करने में असफल रहने पर;
- (iii) डाक द्वारा की जाएगी।

(2) जहां सम्पत्ति का स्वामित्व विवादप्रस्त है या जहां सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता और नोटिस या आदेश की तामील असम्भव बिलम्ब के बिना न की जा सकती हो, वहां नोटिस या आदेश को तामील इसे राजपत्र में प्रकाशित करके, और जहां तक सम्भव हो, उस सम्पत्ति के जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहज दृश्य भाग पर उसकी एक प्रति लगा कर, की जा सकेगी।

सुखाचार में  
विधन  
दालना।

19. इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत या अर्जित किसी सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति के बिना या मुरम्मत करने या नगरपालिका की अनुपालन करने के प्रयोजनों के सिवाय, जानबूझ कर ऐसी सम्पत्ति से संलग्न सुविधा या सुखाचार में विधन नहीं डालेगा। या उसके

साथ स्थानी उपयोग के लिए दी गई किसी वस्तु को न हटाएगा, न नष्ट या बेकार करेगा और न ही सम्पत्ति के लिए दिए गए प्रदाय या सेवा को बन्द करेगा या बन्द करवाएगा ।

20. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि इस द्वारा या इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विविरित की जाएं, सरकार के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी ।

(2) उपर्युक्त (1) के अधीन जानी की गई सभी अधिसूचनाएँ, यथागत्यगत, विधान सभा के समक्ष रखी जाएंगी ।

21. (1) इस अधिनियम या तद्धीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी वात के लिए कोई भी वाद, अभियोगन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम या तद्धीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी वात से हुई या होने के लिए सम्बन्धित किसी नुकसानी के लिए, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, सरकार या सरकार प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

22. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी न्यायालय को, किसी ऐसे मामले में जिसमें सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारण के लिए सशक्त है, अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा आदेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

23. जो कोई भी इस अधिनियम या तद्धीन वनाए गए किसी नियम या इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश के किसी उपबन्ध का उत्तरान करेगा या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के विविधपूर्ण प्रयोग में बाधा डालेगा, वह जुमानि से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, और जब अपराध जाल रहने वाला भग हो, तो अतिरिक्त जुमानि से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके द्वारा अपराध जाल रहता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

24. सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक मध्यस्थ और सरकार द्वारा या सरकार प्राधिकारी द्वारा सशक्त प्रत्येक अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन करते समय, भारतीय दण्ड संहिता 1860, (1860 का 5) की धारा 21 के अर्थ के प्रत्यर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

25. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोगमें को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालके बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए, उपबन्ध किया जा सकेगा,

शक्तियों का प्रत्यागो-जन ।

तद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

सिविल न्या-यालयों की अधिकारिता का बर्जन ।

अपराधों के लिए शास्ति ।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना ।

नियम बनाने की शक्ति ।

## अर्थात् :—

- (क) धारा 3 या धारा 6 के अधीन जांच करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (ग) प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त, संदाय का ढंग और ऐसे प्रतिकर की शर्तें;
- (घ) इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के समक्ष और अपील में कार्यवाहियों की लागत के प्रभाजन में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त;
- (ङ) नोटिस और आदेशों की तामील की रीति;
- (च) किराया और उसकी वसूली; और
- (छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती, यदि उस सत्र के या पूर्वोत्तम आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के, अवसान से पूर्व विधान सभा या उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्षितिपथ  
अधिग्रहणों  
और अर्जनों  
का विधि-  
मान्यकरण।

26. (1) समस्त स्थावर सम्पत्ति, जिसका सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी लोक प्रयोजन के लिए, अधिगृहीत किया जाना तात्पर्यत है, और जिसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व, सरकार या सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या अधिभोग किया गया था, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम्प्रक रूप से अधिगृहीत सम्पत्ति समझी जाएगी। और ऐसा अधिग्रहण, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्शनी या आदेश के होते हुए भी सदैव विधिमान्य समझा जाएगा। मानों कि यह अधिनियम अधिग्रहण की तारीख को और से प्रवृत्त रहा था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहण सम्प्रक रूप से इस अधिनियम के अधीन किया गया था, और इस अधिनियम के सभी उपवन्धु तदनुसार लागू होंगे।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अधिग्रहण की किसी अवधि के लिए ऐसो किसी सम्पत्ति के बारे में प्रतिकर के सदाय के लिए, सभी करार और अधिनियं, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, विधिमान्य होंगे और सदैव विधिमान्य रहे समझे जाएंगे तथा प्रवर्तन में रहेंगे और ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अधिग्रहण को किसी भी अवधि के लिए उस सम्पत्ति में सम्बन्धी प्रतिकर के संदाय को लागू होंगे।

इन्हें देखने के लिए जारी किया गया अधिनियमिति के अधीन, सरकार द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए किया गया स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक अधिग्रहण तात्पर्यत जिसका प्रारम्भ से ठीक पूर्व सरकार या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपयोग किया गया था या दबल लिया गया था, उस अधिनियमिति या आदेश में, जिसके अधीन अर्जन किया गया था, किसी त्रुटि या अविधिमान्यता के होते

(2) राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन, सरकार द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए किया गया स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक अधिग्रहण तात्पर्यत जिसका प्रारम्भ से ठीक पूर्व सरकार या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपयोग किया गया था या दबल लिया गया था, उस अधिनियमिति या आदेश में, जिसके अधीन अर्जन किया गया था, किसी त्रुटि या अविधिमान्यता के होते

हुए भी सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे विधिमात्र्य समझ जाएगा मानों कि उन अधिनियमित या आदेश के उपबन्ध इस धारा में सम्मिलित और अधिनियमित किए गए थे और यह धारा अर्जन की तारीख को और से प्रवर्तन में रही थी।

27. (1) उन नियमों के अधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा इस नियमित बनाए जाएं, किसी अधिगृहीत सम्पत्ति के बारे में, किराए के रूप में देय कोई राशि जो बकाया है, मक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति से उसी रीति में वसूल की जा सकेगी जिसमें भू-राजस्व की बकाया की जाती है।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत सम्पत्ति के अनधिकृत अधिभोग में हो, मक्षम प्राधिकारी विहित रीति में, कथित सम्पत्ति के प्रयोग और अधिभोग के कारण हुई ऐसी नुकसानी निर्धारित कर सकेगा जैसा यह उचित समझे और डाक द्वारा या ऐसे अन्य रूप में नोटिस की तामील द्वारा, जैसा इस नियमित बनाए गए नियमों द्वारा जो विहित किए जाएं, उस व्यक्ति को ऐसे समय में जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया हो, नुकसानी का संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (2) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नुकसानी का संदाय करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, नुकसानी भू-राजस्व की बकाया की वसूली की रीति में वसूल का जा सकेगी।

28. (1) प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि ईंस्ट पंजाब रिक्वीजीशनिंग आॉफ इम्सूबेल प्राप्टरी (टैम्परेरी पॉवर) एक्ट, 1947 (1947 का 17), एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन  
और व्या-  
वृत्तियां।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि जो सम्पत्ति ऐसे निरसन से ठीक पूर्व उक्त अधिनियम में उपबन्धों के अधीन अधिग्रहण के अधीन थी, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिगृहीत सम्पत्ति समझी जाएगी, और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे:-

(क) परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अधिग्रहण किसी कालावधि के लिए किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में प्रतिकर के संदाय के लिए सभी करार और अधिनियम, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, प्रवृत्त बने रहेंगे और ऐसे प्रारम्भ के पश्चात अधिग्रहण की किसी भी कालावधि के लिए उस सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रतिकर के संदाय पर लागू होंगे;

(ख) उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत दिए गए कोई आदेश, जारी की गई अधिमूचनाएं या बनाए गए नियम भी हैं) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए समझ जाएंगे, मानो कि उस दिन, जब ऐसी बात, या कार्रवाई की गई थी, यह अधिनियम प्रवृत्त था।

(3) दि हिमाचल प्रदेश रिक्वीजीशनिंग ऐण्ड ऐक्विजीशन आॉफ इम्सूबेल प्राप्टरी आर्डिनेस, 1978 (1978 का 3) एतद्वारा निरसित किया जाता है ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएग, मानो कि यह अधिनियम 28 जुलाई, 1978 को प्रारम्भ हो गया था।

